नतीजा यह होगा कि दिल्ली में पानी का बहुत बड़ा संकट पैदा होगा, पानी का अकाल पड़ जाएगा। अभी जो वाटर रिसोर्स मंत्रालय है उनका कहना है कि जब पानी बंद हो जाएगा तो ऐसी सूरत में हमने अभी तक कोई अल्टरनेटिव इंतजाम दिल्ली की वाटर सप्लाई के लिए नहीं किया है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि अभी से इसका इंतजाम किया जाना चाहिए क्योंकि यह राजधानी का मामला है, करोड़ों लोगों का मामला है, सभी परिवार इसमें आ जाते हैं, गरीब, झुग्गी झोंपड़ी वाले भी और माननीय सदस्य भी इसमें आते हैं। अभी से सरकार को 20 से 30 करोड़ गैलन पानी का इंतजाम करना चाहिए चाहे यू.पी. से करें या हरियाणा से करे या ट्यूबवैल्स बनाए या रेनी वैल्स बनाए। कोई न कोई अल्टरनेट व्यवस्था होनी चाहिए ताकि राजधानी में पीने के पानी को जो अकाल पैदा होने वाला है वह न आए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश) : महोदया, जो त्यागी जी ने स्पेशल मैंशन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित किया है उससे संबद्ध होते हुए मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली में पेय जल का जो संकट पैदा होने वाला है, ज्यों ज्यों गरमी आती जाएगी तो पानी का संकट भी बढ़ता जाएगा। महोदया, जल ही जीवन है, ऐसा कहा जाता है । इसलिए वह संकट न आने पाए। इसलिए मेरा निवेदन है सरकार से कि पहले से गंभीरता से इस ओर ध्यान देना चाहिए और ऐसा करना चाहिए कि आने वाले दिनों में दिल्ली के निवासियों को पानी के संकट का सामना न करना पड़े।

Allotment of 3 percent Quota in DDA Flats for Members of Parliament

मौलाना अबैदुल्ला खान आज़मी (उत्तर प्रदेश) : शुक्रिया मैडम डिप्टी चेयरपर्सन साहिबा, मैं आपके जरिये एक बहुत अहम मसले की तरफ हुकूमते हिन्द का ध्यान दिलाना चाहता हूं जो हमारे मुल्क के बावकार मेम्बरान पार्लियामेंट हैं उनकी घरेलू परेशानियों से मुतल्लिक है।

उपसभापति : पानी के अलावा ?

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : घरेलू मामला उठा रहे हैं।

उपसभापति : घरेलू मामला कैसे उठा रहे हैं ?

माननीय सदस्य : घर की परेशानी है।

मौलाना अबैदुल्ला खान आज़मी : मेम्बरान पार्लियामेंट की हैसियत से मुल्क की खिदमत कर रहे हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : पार्लियामेंट का अंग्रेजी में तर्जुमा किया जाए तो हाउस का मतलब घर होता है।

मौलाना अबैदुल्ला खान आज़मी : जो लोग रिटायर हो चुके हैं, सादिक कहलाते हैं, यहां से हटने के बाद उनके हालात कुछ इस तरह के होते हैं कि :

हाय क्या चीज गरीबुल वतनी होती है,
बैठ जाता है जहां छांव घनी होती है।

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ भीम अफजल : खासतौर पर जब वह दिल्ली आते हैं।

मौलाना अबैदुल्ला खान आज़मी : दिल्ली में उनकी सियासी एक्टीविटी बने रहने के लिए मुल्क के दीगर इलाकों से वह मुल्क की अवाम के नुमाइन्दे बनकर एक जमाने तक यहां खिदमत करने के बाद चले जाते हैं। पेशतर ऐसे लोग होते हैं जो अपने ही वतन में बैठकर महदूद जद्दोजहद सियासी एतबार से

[मौलाना अोबैदुल्ला खान आजमी]

अवामी मफाद के लिए करते हैं। कुछ खास लोग ऐसे भी हैं जो लोग दिल्ली के मुतल्लिक रहकर मर्कजी हुकूमत और अपोजिशन के लीडरों से तालमेल बनाए हुए मुल्क की तरक्की, अवाम की फला-ओ-बहबूद के लिए शबोरोज मसरुफे अमल रहते हैं। इन तमामतर एम. पीज की एक कॉमन परेशानी हमारे सामने आती है और उस परेशानी को दूर करने के लिए मैं रेलवे को मुबारक देता हूं कि रेलवे ने इस सिलसिले में पहला कदम उठाया। एक्स.एम.पीज के लिए आल इंडिया पास जारी करने का जो फैसला रेलवे ने किया है उस पर रेलवे को गहराई के साथ एम.पीज की समस्याओं को और मुल्क के लोगों के मसाइल को हल करने के लिए जो चीज उन्होंने सोची हैं वह मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। पास देने का बैकग्राऊंड इसके अलावा और क्या हो सकता है कि कंटीन्यू सियासत के साथ वह जुड़े रहें, मुल्क और अवाम की खिदमत करते रहें। मगर दिल्ली आने के बाद दिल्ली में सर छिपाने के लिए जो परेशानी होती है उस परेशानी से मेडम आप भी अच्छी तरह से वाकिफ हैं...

उपसभापति : : अभी तक तो वाकिफ नहीं हूं । अभी तो एक्स एम०पी० बनी नहीं हूं ।

मौलाना अोबैदुल्ला खान आजमी : खुदा करे आप उस परेशानी से वाकिफ न हों । मगर जिस परेशानी से हम वाकिफ हैं आपको वाकिफ कराकर आप के जरिए उन समस्याओं का हल ढूंढना चाहते हैं । मेरी गुजारिश यह है कि एम.पीज के सिलसिले में इसके पहले तीन फीसदी मकान डी.डी.ए. की तरफ से, फ्लैट के तौर पर अलोट होते थे जो किस्त के तौर पर एम.पीज को अदा करना पड़ता था उसके फार्म भी दे दिए जाते थे । इस सिलसिले में मेरी जो जानकारी है उस जानकारी के तहत हमारे आडवाणी जी से लेकर अटल जी तक तमाम लोगों को फ्लैट मिले । इन हजरात ने भी फ्लैट खरीदे । साथ-साथ आर० के सिन्हा साहब, चंद्रिका प्रसाद साहब, दीगर हमारे एक्स-एम.पीज, मिनिस्टर्स इन तमाम सब लोगों ने इस तरह की सुविधाओं में फ्लैट खरीदे थे । उनको यह आसानी थी मुल्क की अवाम की फला-ओ-बहबूद के लिए रहकर दिल्ली में काम कर सकें । इसी के साथ-साथ तारा अपार्टमेंट जो कालकाजी के पास है उसमें दर्जनों एम. पीज ने इस तरह से फ्लैट लिए । उनके लिए आसानी पैदा की गई । आज भी मिस्टर शफी कुरैशी, गवर्नर आफ बिहार, साबिक स्पीकर आफ लोक सभा सरदार हिल्लो साहब, हरि किशोर साहब, साबिक नायब वजीरे खारिजा, इस तरह से और भी बहुत सारे लोग हैं जिन हजरात ने इस तरह की सुविधाओं से फायदा उठाया । मुझे अफसोस से आपके जरिए हुकूमत से यह अर्ज करनी है कि आज भी मैम्बरान के लिए यह परेशानी सामने है । जिस प्रोग्राम में डी.डी.ए. के तहत तीन परसेंट एम. पीज. को फ्लैट दिए जाते थे, वह हुकूमत ने बंद कर दिया । मैं आपके जरिए हुकूमत-ए-हिंद से इस दरवाजे को फिर से खुलवाने की इस्तदा करता हूं ताकि एम. पीज को दिल्ली की सरजमीन पर रहकर सियासी कारोबार का और आवाम की फला-ओ-बहबूद के लिए जद्दोजहद करने का रास्ता मिले । मैडम इसके लिए लोग अपना पैसा जमा करते हैं और धीरे-धीरे 4–5 साल में किस्तवार वह पैसा अदा होता चला जाता है । मुल्क की फला-ओ-बहबूद के लिए एम.पीज काम करने की पोजीशन में आते हैं । और मुल्क की फलाह और बहबूदी के लिए एम.पीज काम करने की पोजीशन में भी आते हैं । क्या परेशानी होती है, इत्तफाक की बात है कि हमारे मिनिस्टर गुलाम नबी आजाद साहब यहां पर बैठे हुए हैं, उनके साथ भी यह घटना घट चुकी है । पिछले दिनों में जब वे पार्लियामेंट के मैम्बर नहीं रहे थे तो यह इत्तफाक उनके साथ भी हुआ और दुश्वारियां पेश आई । उनको नोटिस दिया गया कि मकान खाली करो । वे राजाजी मार्ग पर नं० 1 में रहते थे । उस जमाने में बेहद परेशान और बीमार थे । उनकी बीमारी के बाद उनको [illegible] तरह से परेशानियों

का सावुका हुआ है, इसको अच्छी तरह से महसूस किया जा सकता है ।

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Madam, I would like to associate my. self with him and I want to say something more...

उपसभापति : आप इस पर स्टेटमेंट तो नहीं दे रहे हैं ?, सुओ मोटो स्टेटमेंट ? नहीं तो उस पर कलेरिफिकेशन्स चाल् हो जायेंगे ।

मौलाना अबैदुल्ला खान आज़मी : हमारे बावकार मेम्बर आफ पालियामेंट और बावकार सैन्ट्रल मिनिस्टर के पास भी इत्तफाक से दिल्ली में मकान नहीं था । खुदा जाने अब उनके पास मकान है या या नहीं और अगर है तो मैं उनको मुबारकवाद देता हूं और नहीं है तो उनकी इस परेशानी के तहत तमाम मैम्बरान की परेशानियों को आपके सामने रखना चाहता हूं और सुजारिश करता हूं कि जल्द से जल्द हमारे हाउसिंग मिनिस्ट्री का इस सिलसिले में ध्यान दिलवाया जाय कि वे एम.पीज. की समस्याओं को हल करें । मुझे खुद अच्छी तरह से याद है, इसी हाउस में श्रीमती शीला कौल जी ने यह कहा था कि अगर हाउस एग्री होता है तो हमें इस तरह से मकान देने में कोई परेशानी नहीं है ।

मैडम, मैं एक बात कह कर अपनी बात खत्म करूंगा । जनता पार्टी के जमाने में हाउसिंग मिनिस्टर श्री मुरासोली मारन जी थे और उस वक्त यह मसला आया था । हमारे चैयरमैन डा० शंकर दयाल शर्मा जी ने खुद अपनी चेयर से यह इरशाद फरमाया था कि एम० पीज. की परेशानियों को मारन साहब आपको देखना चाहिए । मिलाजुला कर तमाम लोगों की समस्याओं के पेशेनजर में आपके जरिए हुकूमते हिंद से एक जबर्दस्त डिमान्ड और मुतालबा करता हूं कि इस मसले पर पहली फुरसत में निगाह डाली जाये और एम०पीज० की परेशानियों को हल किया जाय ताकि वे मुल्क के दूर-दराज के लोगों की मुसीबतों का सामना करते हुए उनके लिए जद्दोजहद का अख्तियार कर सकें ।

مولانا عبید اللہ خان اعظمی "اقبال پریشان" : شکریہ میڈم ڈپٹی چیرمین صاحبہ میں آپ کے ذریعہ ایک بہت اہم مسئلہ کی طرف حکومت ہند کا دھیان دلانا چاہتا ہوں جو ہمارے ملک کے باوقار ممبران پارلیمنٹ ہیں ان کی گھریلو پریشانیوں سے تعلق ہے ۔

اُپ سبھاپتی : پانی کے علاوہ ۔

شری سنگھ پریا گوتم : گھریلو معاملات رہے ہیں ۔

اُپ سبھاپتی : گھریلو معاملہ کیسے اٹھا رہے ہیں ۔

ایک معزز ممبر : گھر کی پریشانی ہے ۔

مولانا عبید اللہ خان اعظمی : ممبران پارلیمنٹ کی حیثیت سے ملک کی خدمت کر رہے ہیں ۔

شری غلام نبی آزاد : - پارلیمنٹ کا انگریزی میں ترجمہ کیا جائے تو ہاؤس کا مطلب گھر

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

ہوں کہ ریلوے نے اس سلسلے میں پہلا قدم اٹھایا ایکس ایم پیز کے لئے آل انڈیا پاس جاری کرنے کا جو فیصلہ ریلوے نے کیا ہے اس پر ریلوے کو گہرائی کے ساتھ ایم پیز کی سمسیاؤں کو اور ملک کے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لئے جو چیز انھوں نے سوچی ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ پاس دینے کا بیک گراؤنڈ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے کنٹی نیو سیاست کے ساتھ وہ جڑے رہیں ملک اور عوام کی خدمت کرتے رہیں۔ مگر دلی آنے کے بعد دلی میں سر چھپانے کے لیے جو پریشانی ہوتی ہے اس پریشانی سے میڈم آپ بھی اچھی طرح واقف ہیں.....

اپ سبھاپتی: ابھی تک تو واقف نہیں ہوں۔ ابھی تو ایکس ایم۔ پی بنی نہیں ہوں ۔

مولانا عبیداللہ خاں اعظمی: خدا کرے آپ اس پریشانی سے واقف نہ ہوں مگر جس پریشانی سے ہم واقف ہیں آپ کو واقف کرا کر آپ کے ذریعہ ان سمیاؤں کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں میری گذارش یہ ہے کہ ایم۔ پیز کے سلسلے میں اس کے پہلے تین فیصدی مکان ڈی۔ ڈی۔ اے کی طرف سے فلیٹ کے طور پر الاٹ ہوتے تھے جو قسط کے طور پر ایم۔ پیز کے طور پر ادا کرنا پڑتا تھا۔ اس کے فارم بھی دے دیے جاتے تھے۔ ہوتا ہے۔

مولانا عبیداللہ خان اعظمی: جو لوگ ریٹائر ہو چکے ہیں۔ سابق کہلاتے ہیں۔ یہاں سے ہٹنے کے بعد ان کے حالات کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ . . .

ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے
بیٹھ جاتا ہے جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے

شری محمد افضل عرف م افضل: خاص طور پر جب وہ دلی آتے ہیں۔

مولانا عبیداللہ خان اعظمی: دلی میں ان کی سیاسی ایکٹی ویٹی بنے رہنے کے لئے ملک کے دیگر علاقوں سے وہ ملک کے عوام کے نمائندے بن کر ایک زمانے تک یہاں خدمت کرنے کے بعد چلے جاتے ہیں۔ بیشتر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ہی وطن میں بیٹھ کر محدود جدوجہد سیاسی اعتبار سے عوامی مفاد کے لئے کرتے ہیں۔ کچھ خاص لوگ ایسے بھی ہیں جو لوگ دلی سے متعلق رہ کر مرکزی حکومت اور اپوزیشن کے لیڈروں سے تال میل بنائے ہوئے ملک کی ترقی۔ عوام کی فلاح و بہبود کے لئے شب و روز مصروف عمل رہتے ہیں۔ ان تمام تر ایم پیز کی ایک کامن پریشانی ہمارے سامنے آتی ہے اور اس پریشانی کو دور کرنے کے لئے میں ریلوے کو مبارکباد دیتا

اس سلسلے میں میری جو جانکاری ہے اس جانکاری کے تحت ہمارے ایڈوانی جی سے لے کر اٹل جی تک تمام لوگوں کو فلیٹ ملے۔ ان حضرات نے بھی فلیٹ خریدے۔ ساتھ ساتھ آر۔ کے۔ سنہا صاحب۔ چندریکا پرساد صاحب دیگر ہمارے ایکس ایم پیز منسٹرس ان تمام سب لوگوں نے اسطرح کی سویدھاؤں میں فلیٹ خریدے تھے ان کو یہ آسانی تھی ملک کے عوام کی فلاح و بہبودی کے لیے دلّی میں رہ کر کام کرسکیں اسی کے ساتھ ساتھ تارا اپارٹمنٹ جو کاکا کاجی کے پاس ہے۔ اس میں درجنوں ایم۔ پیز نے اس طرح سے فلیٹ لیے۔ انکے لیے آسانی پیدا کی گئی۔ آج بھی مسٹر شفیع قریشی گورنر آف بہار سابق اسپیکر آف لوک سبھا سردار ڈھلوں صاحب ہری کشور صاحب۔ سابق نائب وزیر خارجہ۔ اس طرح سے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ جن حضرات نے اسطرح کی سویدھاؤں سے فائدہ اٹھایا۔ مجھے افسوس کے ساتھ آپکے ذریعہ حکومت سے یہ عرض کرنا ہے کہ آج بھی ممبران کے لیے یہ پریشانی سامنے ہے جس پروگرام میں ڈی۔ ڈی۔ اے کے تحت تین پرسینٹ ایم۔ پیز کو فلیٹ دیے جاتے تھے وہ حکومت نے بند کردیا۔ میں آپ کے ذریعہ حکومت ہند سے اس دروازہ کو پھر سے کھلوانے کی استدعا کرتا ہوں۔ تاکہ ایم۔ پیز کو دلّی کی سرزمین پر رہ کر سیاسی کاروبار کا اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جدوجہد کرنے کا راستہ ملے۔ میڈم اسکے لیے لوگ اپنا پیسہ جمع کرتے ہیں اور دھیرے دھیرے چار پانچ سال میں قسطوار وہ پیسہ ادا ہوتا چلا جاتا ہے۔ ملک کی فلاح و بہبودی کے لیے ایم۔ پیز کام کرنے کی پوزیشن میں بھی آتے ہیں۔ کیا پریشانی ہوتی ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ ہمارے منسٹر غلام نبی آزاد صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ انکے ساتھ بھی یہ گھٹنا گھٹ چکی ہے۔ پچھلے دنوں میں وہ جب پارلیمنٹ کے ممبر نہیں رہے تھے تو یہ اتفاق سے انکے ساتھ بھی ہوا۔ اور دشواریاں پیش آئیں۔ انکو نوٹس دیا گیا کہ مکان خالی کردو۔ وہ راجہ جی مارگ پر نمبر ۱ میں رہتے تھے۔ اس زمانے میں بے حد پریشان اور بیمار تھے۔ انکی بیماری کے بعد ان کو کس طرح سے پریشانیوں کا سابقہ ہوا ہے۔ اس کو اچھی طرح سے محسوس کیا جاسکتا ہے۔ ہمارے باوقار ممبر آف پارلیمنٹ اور باوقار سینٹرل منسٹر کے پاس بھی اتفاق سے دلّی میں مکان نہیں تھا۔ خدا جانے اب ان کے پاس مکان ہے یا نہیں اور اگر ہے تو میں انکو مبارکباد

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश) : महोदया, इस मांग से सारा सदन सहमत है । सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए ।

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ शीम अफजल: अगर झुग्गी-झोपड़ी को भी हटाया जाता है तो 22 गज का प्लाट गवर्नमेंट की तरफ से और डी.डी.ए. की तरफ से कम्पेंसेशन के तौर पर दिया जाता है । लेकिन वे लोग अवाम के नुमाइंदे, जो चुनकर आते हैं, दिल्ली में, 5-6 साल रहने के बाद अगर वे मैम्बर नहीं रह जाते हैं तो उनके लिए डी.डी.ए. के पास कोई गुंजाइश नहीं है । यह बड़े अफसोस का मकाम है । इस पर गौर करना चाहिए। उनको भी कम से कम कोई आल्टरनेटिव दिया जाना चाहिए । मौलाना आबिद उल्ला खान आजमी जी ने जो कुछ कहा है, मैं भी उससे अपने आप को एसोसिएट करता हूं ।

†श्री मुहम्मद अफ़ज़ल उर्फ़ शीम अफ़ज़ल: अगर झुग्गी-झोपड़ी को भी हटाया जाता है तो 22 गज का प्लाट गवर्नमेंट की तरफ से और डी.डी.ए. की तरफ से कम्पेंसेशन के तौर पर दिया जाता है । लेकिन वे लोग अवाम के नुमाइंदे, जो चुनकर आते हैं, दिल्ली में, 5-6 साल रहने के बाद अगर वे मैम्बर नहीं रह जाते हैं तो उनके लिए डी.डी.ए. के पास कोई गुंजाइश नहीं है । यह बड़े अफसोस का मकाम है । इस पर गौर करना चाहिए। उनको भी कम से कम कोई आल्टरनेटिव दिया जाना चाहिए । मौलाना आबिद उल्ला खान आजमी जी ने जो कुछ कहा है, मैं भी उससे अपने आप को एसोसिएट करता हूं ।

†श्री मुहम्मद अफ़ज़ल उर्फ़ शीम अफ़ज़ल: अगर झुग्गी-झोपड़ी को भी हटाया जाता है तो 22 गज का प्लाट गवर्नमेंट की तरफ से और डी.डी.ए. की तरफ से कम्पेंसेशन के तौर पर दिया जाता है । लेकिन वे लोग अवाम के नुमाइंदे, जो चुनकर आते हैं दिल्ली में, 5-6 साल रहने के बाद अगर वे मैम्बर नहीं रह जाते हैं तो उनके लिए डी.डी.ए. के पास कोई गुंजाइश नहीं है । यह बड़े अफसोस का मकाम है । इस पर गौर करना चाहिए। उनको भी कम से कम कोई आल्टरनेटिव दिया जाना चाहिए । मौलाना आबिद उल्ला खान आजमी जी ने जो कुछ कहा है, मैं भी उससे अपने आप को एसोसिएट करता हूं ।

†श्री मुहम्मद अफ़ज़ल उर्फ़ शीम अफ़ज़ल: अगर झुग्गी-झोपड़ी को भी हटाया जाता है तो 22 गज का प्लाट गवर्नमेंट की तरफ से और डी.डी.ए. की तरफ से कम्पेंसेशन के तौर पर दिया जाता है । लेकिन वे लोग अवाम के नुमाइंदे, जो चुनकर आते हैं दिल्ली में, 5-6 साल रहने के बाद अगर वे मैम्बर नहीं रह जाते हैं तो उनके लिए डी.डी.ए. के पास कोई गुंजाइश नहीं है । यह बड़े अफसोस का मकाम है । इस पर गौर करना चाहिए। उनको भी कम से कम कोई आल्टरनेटिव दिया जाना चाहिए । मौलाना आबिद उल्ला खान आजमी जी ने जो कुछ कहा है, मैं भी उससे अपने आप को एसोसिएट करता हूं ।

†श्री मुहम्मद अफ़ज़ल उर्फ़ शीम अफ़ज़ल: अगर झुग्गी-झोपड़ी को भी हटाया जाता है तो 22 गज का प्लाट गवर्नमेंट की तरफ से और डी.डी.ए. की तरफ से कम्पेंसेशन के तौर पर दिया जाता है । लेकिन वे लोग अवाम के नुमाइंदे, जो चुनकर आते हैं दिल्ली में, 5-6 साल रहने के बाद अगर वे मैम्बर नहीं रह जाते हैं तो उनके लिए डी.डी.ए. के पास कोई गुंजाइश नहीं है । यह बड़े अफसोस का मकाम है । इस पर गौर करना चाहिए। उनको भी कम से कम कोई आल्टरनेटिव दिया जाना चाहिए । मौलाना आबिद उल्ला खान आजमी जी ने जो कुछ कहा है, मैं भी उससे अपने आप को एसोसिएट करता हूं ।

†[ ] Transliteration in Arabic Script,

श्री संघ प्रिय गौतम : मैं इस बात से तो इत्तफाक करता नहीं हूं कि एम. पीज. यहां रह करके पब्लिक की खिदमात करेंगे और सियासी शक फर-मायेंगे । अलबत्ता यह जरूर है कि दूर-दराज से आ कर यहां एयर कंडीशन में रह कर, सब्सीडाइज्ड खाना खाकर और यहां के एसो-आराम करके उनकी जहनियत जरूर ऐसी बन जाती है कि वे दिल्ली में रहें,। इसलिए जो लोग एफोर्ड नहीं कर सकते ...(**व्यवधान**) और मकान नहीं बना सकते उन्हें मकान मिलने चाहिए ।

उपसभापति : अगर आपकी इस मामले में दूसरी राय है तो आप चैयरसाहब से इजाजत मांगकर अपनी राय का इजहार कर दीजिए ।

श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर (मध्य प्रदेश) : अभी जो गौतम जी ने फरमाया है, उसके बारे में मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये हालात उनके साथ हो सकते हैं। दूसरे एम.पीज. के साथ ऐसा नहीं है इनकी हालत दिल्ली में आकर खराब हो गई होगी, लेकिन हम लोगों के साथ ऐसी कोई बात नहीं है ।

श्री संघ प्रिय गौतम : मैं तो सपोर्ट कर रहा हूं कि मकान दिए जाएं । लेकिन मानसिकता ऐसी बन जाती है दिल्ली में रहने के बाद कि दिल्ली छोड़ना नहीं चाहते और यहीं रहना चाहते हैं ।

श्री राम नरेश यादव : इससे तो पूरा सदन सहमत है ।

उपसभापति : मंत्री जी बैठे हैं पार्लियामेंटरी एफेयर्स के, इस सदन के मैम्बरों के मुताल्लिक मामला है, तो मंत्री आप ध्यान दीजिएगा ।

SHRI GHULAM NABI AZAD: I will bring this to the notice of the Ministry concerned.

उपसभापति : आप पर तो वाक्या गुजर चुका है ।

Need to disallow import of cotton

DR. YELMANCHILI SIVAJI (Andhra Pradesh): Madam, on the 24th November last, the Minister of State for Textiles, Mr. Ashok Gehlot, in the course of his reply in the House stated that there would be no import of cotton during the current year. The Cotton Advisory Board, in its meeting of August, 1991, stated that the total production in the country was to the tune of 130 lakh bales and the carry-over stocks were 22.2 lakh bales and, so, the total availability was to the tune of 152.2 lakh bales. As against this, the demand is 108 lakh bales for the mill sector and another 7 lakh bales for the mill-sector . But, on the 23rd January 1992, the Cotton' Textile Board revised its estimates reducing the total availability to 139.12 lakh bales, indicating thereby that import of cotton was warranted. And, Madam, the Textiles Ministry, under pressure from the textile industry, wrote to the Finance Ministry for the release of the necessary foreign exchange to import cotton under the OGL, and, at the intervention of the Prime Minister, the Finance Ministry did not allow the import of cotton nor allow the waiving of the import duty. But the Textiles Ministry did not stop there. They went further and sometime in the month of February, on the 15th or 17th, they went ahead with their proposal to import cotton. But the Present import of cotton is under the Advance Licensing Scheme. Curiously, after announcing that cotton was not going to be imported, the Board members as well as the Indian Cotton Mill Federation reduced the demand to 106 lakh bales stating that there was surplus of cotton in the country. So, it is clear that the Textiles Ministry, on the advice and suggestion of the textile industry, is blowing hot and cold. At one time they say that cotton is not available in the country and, immediately, the nrxt day, they say that there is surplus of cotton in the country! So, this tamasha is going on every year.

Madam, this thing is going on every year, particularly during the harvesting season. During this period, the textile industry and the Textiles